पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद

557. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर राज्यों के राजनीतिक नेताओं ने इस क्षेत्र में उग्रवाद पर काबू पाने के लिए हाल ही में केन्द्र सरकार से पहल करने का आग्रह किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : उत्तर-पूर्वी राज्यों के राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों ने, अपने आपस में और केन्द्रीय एजेन्सियों के मध्य सहयोग की आवश्यकता महसूस करते हुए समन्वित कार्रवाई के लिए एक संयुक्त कार्य क्षेत्र तैयार करने के लिए, कुछ केन्द्रीय मंत्रियों की भागीदारी के साथ, एक बैठक करने का सुझाव दिया है।

केन्द्र सरकार ने इस विचार की सराहना की है और वह उत्तर-पूर्वी राज्यों को सभी प्रकार का सहयोग और सहायता दे रही है ।

पंजाब में जिलों को "अशांत" घोषित किया जाना

558. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अब तक कितने जिलों को "अशांत" घोषित कर दिया गया है ; और

(ख) सरकार द्वारा वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस समय पंजाब सरकार द्वारा राज्य के सभी 12 जिलों को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित किया गया है।

(ख) राज्य में उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने तथा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पंजाब सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं।

Operation Rhino

559. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had launched operation Rhino for curbing the terrorist and secessionist activities in Assam and the North-Eastern region;

(b) if so, what is the extent to which Govt. have succeeded in rounding up the ULFA and other activists separately; and the arms and ammunitions seized from them; and the number of those killed during the operation;

(c) the number of persons who were rounded up in Assam and other affected regions during the period and also those released in exchange of hostages by ULFA and other outfits and the number of civilians including VIPs who were kidnapped and are still in captivity as hostages; and

(d) the period up to which the above operation is likely to continue and the daily expenditure being incurred on Army by the State Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (d) Under Operation Rhino' the Army is providing aid to civil authority in Assam to curb the

terrorist and secessionist activities in Assam. 2649 ULFA and 33 Bodo activists have been apprehended in Assam and other affected regions in this Operation upto 22nd November, 1991. 671 weapons and a sum of Rs. 58.17 lakhs have also been recovered. 9 militants have died as a result of the operation by the Army. 42 ULFA detenues have been released in phases in exchange of hostages. 6 persons are still held captive by the ULFA militants. Since the Army is providing aid to the civil authority in Assam, the duration of operation will depend upon the State Government. The average daily expenditure on Army is Rs. 21 lakh (Twenty-one lakh) approximately.

गोल डाकखाना इत्यादि में यातायात संबंधी प्रबन्ध

560. **श्री विश्वास राव रामराव पाटिल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गोल डाकखाना, पटेल चौक और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पास के चौराहों में भारी यातायात के बावजूद न तो वहां यातायात पुलिस के किसी पुलिसमैन को तैनात किया जाता है और न ही किसी प्रकार के यातायात सिग्नल लगाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार वहां पर यातायात सिग्नल लगाने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो सिग्नल व्यवस्था कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि गोल डाकखाना, पटेल चौक और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चौराहों पर भीड़-भाड़ के समय यातायात पुलिस कार्मिक तैनात किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त गोल डाकखाने पर 7.00 बजे प्रात: से 9.00 बजे प्रात: और 12.00 बजे से 2.00 बजे दोपहर उपिराहनतक यातायात पुलिस कर्मचारी भी तैनात किए जाते हैं । इन चौराहों पर यातायात सिग्नल लगाना, सुचारू सड़क यातायात के लिए व्यवहारिक नहीं समझा गया ।

(ग) और (घ) इस समय ट्रैफिक सिग्नल लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कश्मीर समस्या के संबंध में सुझाव

561. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को कोआर्डिनेशन कमेटी आन कश्मीर नामक एक स्वयंसेवी संगठन से कश्मीर समस्या को सुलझाने के संबंध में एक फार्मूला प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त सुझावों के आधार पर क्या सरकार कश्मीरी उग्रवादियों के दलों से बातचीत करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) कश्मीर के बारे में समन्वयन समिति की ओर से एक अपील प्राप्त हुई है । जिसमें कश्मीर समस्या को हल करने के लिए समिति द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं ।

सरकार ने किसी से भी बात करने की अपनी इच्छा से अवत कराया है